कोविड़ और उसके बाद की परिस्थितियों का सबसे ज्यादा असर मजदूर वर्ग के लोगों पर पड़ा है। एक तरफ उन्हें अपने पुराने काम से हाथ धोना पड़ा है, तो वहीं उनके लिए नए काम के अवसर भी कम हुए हैं। कोविड की वजह से पैदा हुआ संकट मजदूरों के लिए आपदा के समान था। जिसमें उन्हें सबकुछ दांव पर लगाकर गांव वापस लौटना पड़ा। मुसीबत के इस समय में उम्मीद की जा रही थी कि सरकार इन मजदूरों के लिए कुछ ठोस योजनाएं बनाएगी। एक साल बीत जाने के बाद भी सरकार द्वारा कुछ भी ऐसा नहीं किया गया है जिससे लगे कि सरकार ने मजदूर वर्ग को राहत देने के लिए कुछ किया है। देश के सबसे पिछड़े इलाकों में से एक बुंदेलखंड में जहां हर घर से एक या दो सदस्य कमाने के लिए बाहर हैं, वहां संकट और भी गहरा है।

बुंदेलकंड क्षेत्र में खेती अभी भी रोजगार का मुख्य साधन है, जो पिछले दो दशकों से लगातार संकट से जूझ रही है। ऐसे में घर वापस लौटे लोगों का दबाव भी खेती पर आ गया जिसकी वजह से परिवारों की आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई। वापस लौटे मजदूरों को खेती के अलावा सरकारी योजना के तौर पर केवल मनरेगा का ही आसरा था। लेकिन जब काम की जरूरत ज्यादा थी उस वक्त मनरेगा में बहुत सीमित काम मिला। यहां के उपलबद्ध आंकड़ों का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि मनरेगा में सौ दिन काम की कानूनी गारंटी होने के बाद भी सौ दिन काम नहीं मिला। जिसका खामियाजा मजदूर वर्ग के लोगों को अलग-अलग तरीके से चुकाना पड़ रहा है।

कोविद के दौरान सरकार ने इसके लिए एक लाख करोड़ से ज्यादा का बजट भी घोषित किया गया था। जिससे मजदूर वर्ग के लिए कुछ राहत मिली लेकिन इस साल के बजट में की गई कटौती ने मजदूरों के संकट को और बढ़ा दिया है। इसके फलस्वरूप बुंदेलखंड जैसे इलाके जो पलायन की समस्या से जूझ रहे हैं, पलायन की गति को और तेज कर दिया है।

मैं अपनी स्टोरी में मजदूरों की स्थिति को जानने की कोशिश करूंगा कि कोरोना और उसके बाद की परिस्थितियों वे कैसे प्रभावित हुए हैं। उनके लिए सरकार द्वारा क्या योजनाएं चलाई गईं जिससे उनके आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आया हो। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हो रहे हैं जो मुख्य रूप से ग्रामीण आबादी पर केंद्रित हैं। इन चुनावों को कराने का मुख्य आधार ही ये होता है कि ग्रामीण आबादी की समस्याओं को उनके ही स्तर पर हल करने के प्रयास किए जाएं जिससे की वे केंद्र और राज्य की सरकारों पर निर्भर न रहें। मजदूर वर्ग के ज्यादातर लोग ग्रामीण इलाकों से संबंधित होते हैं, ऐसे में पंचायत चुनाव में उनकी क्या हैसियत है? क्या वे पंचायत चुनाव के जरिए जरिए सरकार पर दबाव बनाने की स्थिति में हैं।